रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)-72

REGISTERED No. D. (D.N.) 72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 158] नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 30, 1987/चैत्र 9, 1909

No. 158] NEW DELHI, MONDAY, MARCH 30, 1987/CHAITRA 9, 1909

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, 30 मार्च, 1987

अधिसूचना

सा. का. नि 343(अ)--केन्द्रीय सरकार, राज्यपाल (उपलब्धियां, भत्ते और विशेषाधिकार) अधिनियम, 1982 (1982 का 43) की धारा 13 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:--

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ--(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राज्यपाल (भत्ते और विशेषाधिकार) नियम, 1987 है।

(2) ये 1 अप्रैल, 1987 को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं--इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) "अधिनियम" से राज्यपाल (उपलब्धियां, भत्ते और विशेषाधिकार) अधिनियम, 1982 (1982 का 43) अभिप्रेत है,

(ख) किसी विशिष्ट राज्य के किसी राज्यपाल के "पदीय आवास" से इन नियमों की अनुसूची-1 के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट तत्स्थानी आवास अभिप्रेत है,

(ग) "अनुसूची" से इन नियमों में उपाबद्ध अनुसूची अभिप्रेत है;

(घ) उन शब्दों और पदों के जो इसमें प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं, वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में हैं।

3 पदीय आवासों के साज सामान का नवीकरण--(1) प्रत्येक राज्यपाल को, उसके पदीय आवास (आवासों) के साज सामान के नवीकरण में किए गए वास्तविक व्यय के बराबर समय-समय पर, अनुसूची 1 के स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट अधिकतम रकम के अधीन रहते हुए, भत्ता संदत्त किया जाएगा :

परन्तु यदि, जब राज्यपाल पद ग्रहण करता है तब वह अवधि जो उसके पूर्ववर्ती द्वारा (जिसके अंतर्गत राज्यपाल के कृत्यों का निर्वहन करने के लिए नियुक्त किए गए व्यक्ति नहीं है) पद ग्रहण किए जाने के बाद बीत गई है, पांच वर्ष से कम है तो इस प्रकार विनिर्दिष्ट रकम में से उतनी रकम कम कर दी जाएगी जितनी राष्ट्रपति आदेश द्वारा अवधारित करे :

परन्तु यह और कि ऐसे राज्यपालों की दशा में, जो इन नियमों के प्रारंभ के ठीक पूर्व पद धारण किए हुए हैं उन्हें उनकी संपूर्ण पदावधि के दौरान अनुज्ञेय रकम उतनी होगी जितनी राष्ट्रपति आदेश द्वारा अवधारित करे।

(2) इस नियम के उपबंध, भारत के संविधान के अनुच्छेद 160 के अधीन राज्यपाल के कृत्यों का निर्वहन करने के लिए नियुक्त किए गए व्यक्तियों को लागू नहीं होंगे।

4. गृह्य स्थापन:--(1) पदीय आवास में गृह्य स्थापन के अधिकारियों और कर्मचारिवृन्द की कुल संख्या उतनी होगी जितनी राष्ट्रपति, समय-समय पर, आदेश, द्वारा विहित करे और उनके वेतनमान, भत्ता और अन्य उपलब्धियां तथा सुविधाएं वे होंगी जो संबंधित राज्य में तत्समान पदों पर के राज्य सरकार के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को समय-समय पर, अनुज्ञेय हैं।

(2) गृह्य स्थापन के अधिकारी और कर्मचारिवृन्द किराया वाससुविधा के हकदार होंगे और ऐसे अधिकारी और कर्मचारिवृन्द जिन्हें कोई सरकारी वाससुविधा उपलब्ध नहीं की गई है उन्हें संबंधित राज्य सरकार में कार्य कर रहे तत्समान पदों पर के अधिकारियों और कर्मचारियों को अनुज्ञेय दरों पर मकान किराया भत्ता अनुज्ञात किया जाएगा और ऐसे मामलों में वेतन पर दस प्रतिशत प्रथम भार की प्रतिपूर्ति भी राज्यपाल के भत्तों से की जाएगी।

(3) गृह्य स्थापन के कर्मचारिवृन्द को प्रतिकाल भत्ता अनुज्ञेय नहीं होगा।

(4) गृह्य स्थापन के ऐसे अधिकारी और कर्मचारिवृन्द को, जिन्हें सरकारी वास-सुविधा उपलब्ध की गई है, निःशुल्क विद्युत और पानी की व्यवस्था राज्पाल द्वारा समय-समय पर अधिकथित सीमा के अधीन रहते हुए, की जाएगी किन्तु ऐसी सीमा विद्युत और पानी दोनों के प्रदाय के लिए कर्मचारिवृन्द के सदस्यों के वेतन के $6\frac{1}{2}\%$ से अधिक नहीं होगी:

परन्तु $6\frac{1}{2}\%$ की सीमा में से विद्युत प्रभार किसी भी दशा में 5% से अधिक नहीं होंगे।

(5) उपनियम (4) में विनिर्दिष्ट सीमा से अधिक विद्युत और पानी के उपभोग पर कोई व्यय, यथास्थिति संबंधित अधिकारी या कर्मचारिवृन्द के सदस्य द्वारा वहन किया जाएगा।

(6) गृह्य स्थापन के किसी सदस्य को, निजी प्रयोजनों के लिए राजकीय परिवहन का निःशुल्क उपयोग करने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा :--

परन्तु गृह्य स्थापन के कर्मचारिवृन्द को सरकारी यान का प्रायिक प्रभारों का संदाय किए जाने पर, यानों की उपलभ्यता के अधीन रहते हुए, उपयोग करने के लिए अनुज्ञात किया जा सकेगा।

(7) गृह्य स्थापन के कर्मचारीवृन्द ऐसे पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति फायदों के जिनके अंतर्गत चिकित्सीय सुविधा है जो संबंधित राज्य सरकार के तत्समान पदों पर के कर्मचारियों को अनुज्ञात हैं, हकदार होंगे।

(8) उपनियम (1) के अधीन उपगत किया जाने वाला व्यय राज्यपाल के भत्तों का एक भाग होगा और पृथक रूप से "गृह्य स्थापन" उपशीर्ष के अधीन निकाला जाएगा।

5. राज्यपाल के सचिवालय आदि पर व्यय:--(1) गृह्य स्थापन के अतिरिक्त, राज्यपाल, एक पृथक सचिवीय कर्मचारिवृन्द का हकदार होगा जिसकी संबंधित राज्य सरकार द्वारा व्यवस्था की जाएगी।

(2) राज्यपाल के सचिवालय के स्थापन पर व्यय और गृह्य स्थापन के कर्मचारिवृन्द की पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति फायदों पर व्यय जिनके अंतर्गत चिकित्सीय सुविधाएं हैं, संबंधित राज्य की संचित निधि पर भारित होंगे।

(3) उप नियम (2) में निर्दिष्ट व्यय राज्यपाल के भत्तों का भाग नहीं होगा।

6. राज्यपाल के भत्ते:--(1) इस दृष्टि से कि राज्यपाल अपने पद के कर्तव्यों का सुविधापूर्वक और गरिमा से निर्वहन कर सके, राज्यपाल को निम्नलिखित भत्ते या अनुदान प्रतिवर्ष संदत्त किए जाएंगे ; अर्थात्:--

(क) सत्कार भत्ता--कला, संस्कृति और संगीत के संरक्षण के लिए खर्च किया जाएगा और इस उपशीर्ष के अधीन भत्ते का खर्च न किया कोई भी भाग उस वित्तीय वर्ष के अंत में जिससे वह संबंधित है, व्ययगत हो जाएगा ;

(ख) आतिथ्य अनुदान--सरकारी अतिथियों के आतिथ्य व्ययों की पूर्ति करने के लिए होगा और इस उपशीर्ष के अधीन अनुदान का खर्च न किया गया कोई भी भाग उस वित्तीय वर्ष के अंत में जिससे वह संबंधित है, व्ययगत हो जाएगा।

(ग) कार्यालय व्यय भत्ता--निम्नलिखित मदों पर व्यय की पूर्ति करने के लिए होगा, अर्थात्:--

(i) टेलीफोन प्रभार ; (ii) सरकारी डाक टिकट ; (iii) पुस्तकें और नियत कालिक पत्रिकाएं ; (iv) लेखन सामग्री और मुद्रण - (v) मोटर साइकिलों, स्कूटरों और साइकिलों का अनुरक्षण जिसके अंतर्गत इन यानों के लिए पी. ओ. एल. भी है ; (vi) प्रकीर्ण व्यय :

परन्तु साइकिलों, स्कूटरों या मोटर साइकिलों के क्रय करने संबंधी किसी व्यय की सीधे राज्य सरकार द्वारा पूर्ति की जाएगी ;

(घ) संविदात्मक भत्ता--निम्नलिखित मदों के संबंध में व्यय के लिए उपयोग किया जाएगा, अर्थात् :-(i) विशेष लेखन सामग्री , (ii) छोटी आकस्मिकताएं ; (iii) खेलकूद ; (iv) जलाने की लकडी ; (v) भेंट; (vi) साबुन, सफाई सामग्री, कीटनाशक; (vii) वर्दियां ; (viii) पी. ओ. एल. (पर्यटन व्ययों से भिन्न व्यय) ; (ix) कारों का अनुरक्षण; (x) पुस्तकालय ; और (xi) अन्य प्रकीर्ण व्यय ।

(ङ) साज-सामान के अनुरक्षण और मरम्मत के लिए अनुदान--पदीय आवास/आवासों के साज सामान के अनुरक्षण और मरम्मत के लिए और/या फर्नीचर की नई मदों के क्रय के लिए उपयोग किया जाएगा, परन्तु अधिकतम रकम इस उपशीर्ष के अधीन विनिर्दिष्ट रकम से अधिक नहीं होगी ;

(च) पर्यटन व्यय अनुदान--राज्यपाल के पर्यटक व्ययों के लिए और राज्यपाल के पर्यटनों के लिए उपयोग की गई पदीय आवास (आवासों) की कारों के लिए पी. ओ. एल. संबंधी व्यय के लिए उपयोग किया जाएगा।

(2) उप नियम (1) के अधीन भिन्न-भिन्न उपशीर्षों के अंतर्गत अनुज्ञेय रकम अनुसूची-2 में विनिर्दिष्ट के अनुसार होगी।

(3) (क) निम्नलिखित उपशीर्षों के अंतर्गत कोई पुनर्विनियोजन अनुज्ञेय नहीं होगा :--

(i) सत्कार भत्ता ; (ii) आतिथ्य भत्ता ; (iii) कार्यालय व्यय ; (iv) पदीय आवास (आवासों) के साज-सामान का अनुरक्षण और मरम्मत ;

(ख) राज्यपाल, अनुसूची-2 के स्तंभ (6) और स्तंभ (7) में विनिर्दिष्ट अधिकतम रकम को बढ़ाए बिना, जहां आवश्यक हो, उपशीर्ष "संविदात्मक भत्ता" से उपशीर्ष "पर्यटन व्यय" में और उपशीर्ष "पर्यटन व्यय" से उपशीर्ष "संविदात्मक भत्ता" मे पुनर्विनियोजित कर सकेगा।

(4) अनुसूची 2 में के कार्यालय व्ययों, साज-सामान के अनुरक्षण और मरम्मत, संविदात्मक भत्ते और पर्यटन व्ययों से संबंधित उपशीर्ष

के अधीन विनिर्दिष्ट रकम किसी भी वर्ष में, उन्हीं उपशीर्ष के अधीन पूर्ववर्ती वर्षों में व्यय न की गई रकम तक बढ़ाई जा सकेगी ।

7. पदीय आवास (आवासों) के अनुरक्षण के लिए भत्ते:—राज्यपाल को विभिन्न उपशीर्षों के अधीन जो अनुसूची 3 में विनिर्दिष्ट किए गए हैं पदीय आवास (आवासों) के अनुरक्षण के लिए प्रत्येक वर्ष ऐसे भत्ते भी संदत्त किए जाएंगे :

परन्तु राज्यपाल, उक्त अनुसूची के स्तंभ (7) में विनिर्दिष्ट अधिकतम रकम को बढ़ाए बिना, जहां आवश्यक हो, उसके एक उपशीर्ष से दूसरे उपशीर्ष में पुनर्विनियोजित कर सकेगा :

परन्तु यह और कि उक्त अनुसूची के स्तंभ (7) में विनिर्दिष्ट अधिकतम रकम, किसी भी वर्ष में, पूर्ववर्ती वर्षों में व्यय न की गई रकम तक बढ़ाई जा सकेगी ।

8. पद ग्रहण या पद रिक्त करने पर यात्रा भत्ता:—(1) राज्यपाल को, अपने लिए और अपने कुटुम्ब के सदस्यों के लिए तथा अपनी और अपने कुटुम्ब की चीजबस्त के परिवहन के लिए यात्रा भत्ते के रूप में अधिनियम की धारा 9 में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए यात्रा करने में उपगत वास्तविक व्ययों के बराबर भत्ते का संदाय किया जाएगा ।

(2) उपनियम (1) के अधीन उपगत किया जाने वाला व्यय संबंधित राज्य की संचित निधि पर भारित होगा किन्तु राज्यपाल के भत्तों का भाग नहीं होगी ।

9. छुट्टी.—राष्ट्रपति, उतनी अवधि के लिए राज्यपाल को छुट्टी प्रदान कर सकेगा, जितनी वह आवश्यक समझे ।

10. चिकित्सीय परिचर्या और उपचार:—(i) राज्यपाल और उनके कुटुम्ब के सदस्य अखिल भारतीय सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम, 1954 के अधीन अखिल भारतीय सेवा के उच्चतम ग्रेड के सदस्यों को लागू मापमान और शर्तों पर निःशुल्क चिकित्सीय परिचर्या वास-सुविधा और उपचार के हकदार होंगे ।

(2) भारत से बाहर कर्तव्य पर, राज्यपाल निःशुल्क ऐसी चिकित्सीय परिचर्या, वास-सुविधा और उपचार का हकदार होगा जो उस स्थान पर या उपचार के स्थान पर भारतीय मिशन के प्रधान को अनुज्ञेय हो ।

(3) राज्य सरकार, राज्यपाल और उसके कुटुम्ब के सदस्यों के लिए चिकित्सा सुविधाओं के बारे में पर्याप्त उपबंध करेगी और इस मद में व्यय राज्य की संचित निधि पर भारित होगा तथा राज्यपाल के भत्तों का भाग नहीं होगा ।

(4) भूतपूर्व राज्यपाल और उसके कुटुम्ब की चिकित्सीय परिचर्या, वास-सुविधा और उपचार, समय-समय पर भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा बनाए गए नियमों/आदेशों द्वारा शासित होगा ।

11. पर्यटन और अन्य यात्राएं : (1) राज्यपाल, राज्य के भीतर अपनी सभी यात्राओं के लिए रेल सैलून की अध्यपेक्षा करने का हकदार होगा और अपने साथ तीन से अनधिक व्यक्ति, उनके लिए किसी किराए का संदाय किए बिना, ले जाने का हकदार होगा ।

(2) कर्तव्य और उपनियम (1) के अधीन सैलून की अध्यपेक्षा करने के व्यय की "पर्यटन व्यय" उपशीर्ष से पूर्ति की जाएगी ।

(3) यदि, रेल द्वारा राज्य के भीतर अपनी यात्रा के लिए राज्यपाल उपनियम (1) के अधीन सैलून की अध्यपेक्षा न करने का चयन करता है तो वह चार वर्थ वाले कंपार्टमेंट या कूपे में, चाहे वह प्रथम श्रेणी वातानुकूलित हो या प्रथम श्रेणी, यात्रा करने का हकदार होगा और ऐसी यात्रा के दौरान राज्यपाल, चार-वर्थ वाले कंपार्टमेंट की दशा में तीन व्यक्ति और कूपे की दशा में एक व्यक्ति, किसी अतिरिक्त प्रभार के बिना, अपने साथ ले जाने का हकदार होगा ।

(4) राज्य के बाहर के स्थानों के लिए सरकारी कार्य से संबंधित यात्राओं के लिए राज्यपाल चार-वर्थ वाले कंपार्टमेंट या कूपे में, चाहे वह प्रथम श्रेणी वातानुकूलित हो या प्रथम श्रेणी, यात्रा करने का हकदार होगा और ऐसी यात्रा के दौरान चार-वर्थ वाले कंपार्टमेंट की दशा में तीन व्यक्ति और कूपे की दशा में एक, व्यक्ति किसी अतिरिक्त प्रभार के बिना, अपने साथ ले जाने का हकदार होगा ।

(5) राज्यपाल का पति या पत्नी कला, संस्कृति, विज्ञान और साहित्य से संबंधित किसी संगठन या संगम द्वारा आयोजित समारोहों में भाग लेने के लिए रेल द्वारा राज्य के भीतर यात्रा कर सकेगा और उस प्रयोजन के लिए प्रथम श्रेणी वातानुकूलित या प्रथम श्रेणी कंपार्टमेंट में एकल सीट आरक्षित करा सकेगा और ऐसी यात्राओं के लिए व्यय की—

(i) "पर्यटन व्यय" उपशीर्ष से पूर्ति की जाएगी, यदि उस संगठन या संगम के साथ वह किसी भी हैसियत में सहयोजित नहीं है ; या

(ii) उस संगठन या संगम द्वारा पूर्ति की जाएगी, जिसके साथ वह किसी भी हैसियत में सहयोजित है ; परन्तु यह सुविधा राज्यपाल के पति या पत्नी की निजी यात्राओं के लिए उपलब्ध नहीं होगी ।

(6) कर्तव्य पर (न कि गैर सरकारी कार्य पर) यात्रा करने वाला कोई राज्यपाल, वायुयान द्वारा यात्रा करने का हकदार होगा और ऐसी किसी यात्रा के दौरान सरकारी व्यय पर अपने साथ एक व्यक्ति को ले जाने का हकदार होगा ।

(7) कोई राज्यपाल, उपनियम (6) के अधीन कर्तव्य पर वायुयान द्वारा यात्रा करते समय, अपने विवेकानुसार एक्जीक्यूटिव श्रेणी में यात्रा कर सकेगा और ऐसी यात्रा के दौरान उसके साथ जाने वाला व्यक्ति, राज्यपाल के पति या पत्नी को छोड़कर, जो एक्जीक्यूटिव श्रेणी में यात्रा कर सकेगी, स्टैंडर्ड श्रेणी में ही यात्रा करने का हकदार होगा ।

(8) कोई राज्यपाल सरकारी व्यय पर वायुयान द्वारा निजी कार्य के संबंध में यात्रा करने का हकदार नहीं होगा और न सरकारी व्यय पर अपने साथ किसी व्यक्ति को ही ले जाने का हकदार होगा ।

(9) कोई राज्यपाल राज्य के बाहर अपनी निजी यात्रा के संबंध में चार-वर्थ कंपार्टमेंट या कूपे में चाहे प्रथम श्रेणी वातानुकूलित हो या प्रथम श्रेणी, यात्रा कर सकेगा और वह—

(i) अपने किराए के अतिरिक्त समुचित श्रेणी की दो वर्थ के किराए का, यदि वह चार-वर्थ वाले कंपार्टमेंट में यात्रा करता है ;

(ii) अपने किराए का, यदि वह कूपे में यात्रा करता है;

(iii) यथास्थिति, कंपार्टमेंट या कूपे के आरक्षण प्रभारों और यात्रा के दौरान उपगत किसी अन्य व्यय का, संदाय करेगा ।

(10) उपनियम (9) के अधीन की गई किसी यात्रा के लिए केवल एक किराए के व्यय की पूर्ति सरकार द्वारा "पर्यटन व्यय" उपशीर्ष से की जाएगी और उस किराए के बदले में राज्यपाल अपने साथ किसी भी ऐसे व्यक्ति को ले जा सकेगा, जिसके लिए उसके कुटुम्ब का सदस्य होना आवश्यक नहीं है ।

(11) यदि कोई राज्यपाल अपने पदीय कर्तव्यों से असंबद्ध किसी कार्य के संबंध में, अर्थात् किसी आयोग, समिति या किसी अन्य संगठन के अध्यक्ष या सदस्य के रूप में कोई यात्रा करता है तो ऐसी यात्राओं पर उपगत व्यय "पर्यटन व्यय" उपशीर्ष में से विकल्पनीय नहीं होगा और ऐसे व्यय की उसी स्रोत में से पूर्ति की जाएगी जिसमें से आयोग, समिति या किसी अन्य संगठन के अन्य व्यय की पूर्ति की जाती है ।

(12) जहां किसी राज्य में कोई रेल स्टेशन या विमानपत्तन नहीं है, वहां किसी पड़ोसी राज्य में स्थित निकटतम रेल स्टेशन या

विमानपत्तन में पहुंचने के लिए राज्यपाल द्वारा या उसके पति या पत्नी द्वारा निजी प्रयोजनों के लिए यात्रा की जाती है तो वह शासकीय यात्रा समझी जाएगी ।

12. राज्यपाल के साथ जाने वाले गृह्य स्थापन के यात्रा भत्ते और दैनिक भत्ते की हकदारी – (1) राज्य के भीतर या राज्य के बाहर राज्यपाल की यात्राओं के संबंध में, चाहे शासकीय हों या निजी राज्यपाल के साथ जाने वाले उसके गृह्य स्थापन के किसी भी सदस्य को कर्तव्य पर माना जाएगा और वह राज्य सरकार के नियमों के अधीन अनुज्ञेय यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ता प्राप्त करने का हकदार होगा ।

(2) राज्यपाल के पति या पत्नी के साथ जाने वाले राज्यपाल के गृह्य स्थापन के किसी भी सदस्य को केवल राज्य के भीतर उसकी यात्रा के दौरान कर्तव्य पर माना जाएगा और वह राज्य सरकार के नियमों के अधीन अनुज्ञेय यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ता प्राप्त करने का हकदार होगा :

परन्तु राज्यपाल के कुटुम्ब के किसी सदस्य के या राज्यपाल के निजी अतिथियों के साथ जाने वाले राज्यपाल के गृह्य स्थापन के किसी सदस्य को कोई यात्रा भत्ता या दैनिक भत्ता अनुज्ञेय नहीं होगा ।

13. राज्यपाल, आदि द्वारा मोटरयानों का उपयोग—(1) पदीय आवास (आवासों) के मोटरयानों द्वारा राज्य के बाहर राज्यपाल द्वारा की गई किन्हीं निजी यात्राओं के लिए राज्य सरकार की स्टाफ कार दरों पर राज्यपाल द्वारा संदाय किया जाएगा ।

(2) राज्यपाल के पति या पत्नी केवल राज्य के भीतर पदीय आवास (आवासों) के मोटरयानों का निःशुल्क उपयोग करने की हकदार होगी और राज्य के बाहर उसकी यात्राओं के लिए, यदि शासकीय कर्तव्य पर राज्यपाल के साथ नहीं है तो राज्य सरकार की स्टाफ कार दरों पर राज्यपाल द्वारा संदाय किया जाएगा ।

(3) राज्यपाल के कुटुम्ब के किसी अन्य सदस्य को या राज्यपाल के निजी अतिथियों को, जो राज्यपाल या राज्यपाल के पति या पत्नी के साथ नहीं है, राज्य के भीतर पदीय आवास (आवासों) के मोटरयानों का उपयोग करना अनुज्ञात किया जा सकेगा और ऐसी यात्राओं के लिए प्रभारों का राज्य सरकार की स्टाफ कार दरों पर राज्यपाल द्वारा संदाय किया जाएगा ।

14. निर्वचन :– यदि इन नियमों के निर्वचन के संबंध में कोई प्रश्न उठता है तो वह केन्द्रीय सरकार को निर्देशित किया जाएगा जो उसका विनिश्चय करेगी ।

15. निरसन और व्यावृत्ति :– (1) इन नियमों के प्रारंभ के ठीक पूर्व प्रवृत्त सभी आदेश, जहां तक उनका संबंध इन नियमों में उपबंधित विषयों से है, निरसित किए जाते हैं ।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी यह है कि इस प्रकार निरसित आदेशों के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई इन नियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई समझी जाएगी ।

अनुसूची 1

राज्यपालों के पदीय आवास (आवासों) और उनके साज सामान के नवीकरण के लिए अनुज्ञेय अधिकतम रकम

(नियम 3 देखिए)

राज्य का नाम	पदीय आवास	साज-सामान के नवीकरण के लिए राज्यपालों को अधिकतम भत्ता (रुपयों में)
1	2	3
1. आन्ध्र प्रदेश	हैदराबाद स्थित राजभवन	2,10,000
2. अरुणाचल प्रदेश	ईटानगर स्थित राजभवन	2,40,000
3. असम	गुवाहाटी स्थित राजभवन	2,40,000
4. बिहार	पटना और रांची स्थित राजभवन	3,05,400
5. गुजरात	गांधीनगर स्थित राजभवन और अहमदाबाद स्थित राजभवन एनेक्सी	1,80,000
6. हरियाणा	चण्डीगढ़ स्थित राजभवन	1,50,000
7. हिमाचल प्रदेश	शिमला स्थित राजभवन	1,80,000
8. कर्नाटक	बंगलौर और मैसूर स्थित राजभवन	1,50,000
9. केरल	तिरुवनन्तपुरम स्थित राजभवन	1,50,000
10. मध्य प्रदेश	भोपाल और पंचमढ़ी स्थित राजभवन	1,80,000
11. महाराष्ट्र	मुम्बई, गणेशखिन्ड (पुणे) और नागपुर स्थित राजभवन	9,00,000

1	2	3
12. मणिपुर	इम्फाल स्थित राजभवन	2,40,000
13. मेघालय	शिलांग स्थित राजभवन	2,40,000
14. मिजोरम	एजवाल स्थित राजभवन	2,40,000
15. नागालैंड	कोहिमा स्थित राजभवन	1,20,000
16. उड़ीसा	भुवनेश्वर स्थित राजभवन	2,76,000
17. पंजाब	चण्डीगढ़ स्थित राजभवन	1,80,000
18. राजस्थान	जयपुर और माउंट आबू स्थित राजभवन	1,50,000
19. सिक्किम	गंगटोक स्थित राजभवन	1,80,000
20. तमिलनाडु	गुंइडी और उटकमंड स्थित राजभवन	3,90,000
21. त्रिपुरा	अगरतला स्थित राजभवन	1,20,000
22. उत्तर प्रदेश	लखनउ और नैनीताल स्थित राजभवन	5,59,800
23. पश्चिम बंगाल	कलकत्ता और दार्जिलिंग स्थित राजभवन	5,25,000

अनुसूची—2

(कुछ मामलों के संबंध में राज्यपालों के भत्ते)

(नियम 6 देखिए)

राज्य का नाम	आतिथ्य व्यय	सत्कार भत्ता	कार्यालय व्यय	पदीय आवास (आवासों) के साज-सामान का अनुरक्षण और मरम्मत	संविदात्मक भत्ता	पर्यटन व्यय	योग
1	2	3	4	5	6	7	8
	रु.	रु.	रु.	रु.	रु.	रु.	रु.
1. आंध्र प्रदेश	1,08,000	30,000	1,80,00	72,000	3,24,000	4,80,000	11,94,000
2. अरूणाचल प्रदेश	36,000	9,0000	90,000	36,000	1,44,000	5,10,000	8,25,000
3. असम	45,000	15,000	1,50,000	60,000	1,80,000	3,30,000	7,80,000
4. बिहार	45,000	15,000	1,80,000	84,000	1,92,000	3,48,000	8,64,000
5. गुजरात	1,08,000	30,000	1,80,000	90,000	3,60,000	3,00,000	10,68,000
6. हरियाणा	60,000	18,000	1,20,000	60,000	3,00,000	2,40,000	7,98,000
7. हिमाचल प्रदेश	60,000	18,000	1,20,000	90,000	3,00,000	2,40,000	8,28,000
8. कर्नाटक	60,000	30,000	1,50,000	60,000	6,00,000	3,00,000	12,00,000
9. केरल	54,000	18,000	1,20,000	60,000	3,30,000	1,80,000	7,62,000
10. मध्य प्रदेश	72,000	24,000	1,80,000	60,000	3,00,000	30,07,000	9,36,000
11. महाराष्ट्र	1,80,000	30,000	1,80,000	3,00,000	9,00,000	7,50,000	23,40,000
12. मणिपुर	36,000	9,000	90,000	36,000	1,44,000	2,55,000	5,70,000
13. मेघालय	36,000	9,000	90,000	36,000	1,44,000	2,55,000	5,70,000
14. मिजोरम	36,000	9,000	90,000	36,000	1,44,000	5,10,000	8,25,000
15. नागालैण्ड	24,000	9,000	90,000	15,000	2,40,000	2,50,000	6,28,000
16. उडीसा	45,000	15,000	1,20,000	60,000	1,88,400	2,82,000	7,10,400
17. पजाब	60 000	18,000	1,20,000	60,000	3,00,000	3,00,000	8,58,000
18. राजस्थान	72,000	18,000	1,20,000	60,000	3,00,000	3,00,000	8,70,000
19. सिक्किम	45,000	18,000	1,20,000	36,000	1,50,000	2,50,000	6,19,000
20. तमिलनाडु	1,20,000	30,000	1,80,000	1,50,000	6,00,000	3,00,000	13,80,000
21. त्रिपुरा	18,000	5,000	90,000	12,000	2,40,000	2,60,000	6,25,000
22. उत्तर प्रदेश	1,14,000	30,000	1,80,000	90,000	3,00,000	6,96,000	14,10,000
23 पश्चिम बंगाल	1,35,000	30,000	1,80,000	1,50,000	7,80,000	2,76,000	15,51,000

अनुसूची—3

पदीय आवासों के अनुरक्षण के लिए भत्ता

(नियम 7 देखिए)

राज्य का नाम	मरम्मत	उद्यान	विद्युत	पानी	सुधार	योग
1	2	3	4	5	6	7
	रु.	रु.	रु.	रु.	रु.	रु.
1. आन्ध्र प्रदेश	2,40,000	60,000	2,16,000	60,000	84,000	6,60,000
2. अरुणाचल प्रदेश	2,60,000	1,20,000	1,44,000	21,000	45,000	5,90,000
3. असम	94,200	78,600	33,600	33,600	90,000	3,30,000
4. बिहार	3,72,000	1,38,000	84,000	57,000	1,50,000	8,01,000
5. गुजरात	2,10,000	1,56,000	1,20,000	72,000	72,000	6,60,000
6. हरियाणा	1,17,000	1,17,000	81,000	54,000	54,000	4,23,000
7. हिमाचल प्रदेश	1,20,000	1,08,000	90,000	33,000	30,000	3,81,000
8. कर्नाटक	3,00,000	3,00,000	1,50,000	1,50,000	3,00,000	12,00,000
9. केरल	2,28,000	1,20,000	90,000	42,000	1,20,000	6,00,000
10. मध्य प्रदेश	1,74,000	1,56,000	60,000	6,000	60,000	4,56,000
11. महाराष्ट्र	22,62,000	3,00,000	4,08,000	3,00,000	3,60,000	36,30,000
12. मणिपुर	2,60,000	1,20,000	1,44,000	21,000	45,000	5,90,000
13 मेघालय	2,60,000	1,20,000	1,44,000	21,000	45,000	5,90,000
14. मिजोरम	2,60,000	1,20,000	1,44,000	21,000	45,000	5,90,000
15. नागालैंड	1,08,000	90,000	90,000	12,000	45,000	3,45,000
16. उड़ीसा	1,53,000	59,400	1,17,000	38,400	39,000	4,06,800
17. पंजाब	1,56,000	1,56,000	1,08,000	72,000	72,000	5,64,000
18. राजस्थान	1,74,000	1,56,000	60,000	30,000	60,000	4,80,000
19. सिक्किम	30,000	60,000	30,000	18,000	30,000	1,68,000
20. तमिलनाडु	6,18,000	3,84,000	3,30,000	1,02,000	3,00,000	17,34,000
21. त्रिपुरा	1,80,000	1,20,000	1,44,000	42,000	1,20,000	6,06,000
22. उत्तर प्रदेश	4,80,000	2,70,000	1,20,000	90,000	1,80,000	11,40,000
23. पश्चिम बंगाल	17,94,000	4,80,000	2,70,000	9,00,000	96,000	35,40,000

[फा. सं. 20/1/82-एस. एण्ड पी. (ii)]

आई. पी. गुप्ता, अपर सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th March, 1987

G.S.R. 343(E).—In exercise of the powers conferred by section 13 of the Governors (Emoluments, Allowances and Privileges) Act, 1982 (43 of 1982), the Central Government hereby makes the following rules, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Governors (Allowances and Privileges) Rules, 1987.

(2) They shall come into force on the 1st day of April, 1987.

2. Definition.—In these rules, unless the context otherwise requires—

(a) "Act" means the Governors (Emoluments, Allowances and Privileges) Act 1982 (43 of 1982);

(b) "Official residence" in relation to a Governor of a particular State means the corresponding residence(s) specified in column (2) of Schedule I to these rules;

(c) "Schedule" means a Schedule appended to these rules;

(d) words and expressions used herein and not defined shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.

3. Renewal of furnishings of official residences.—(1) There shall be paid, from time to time, to each Governor an allowance equal to the actual expenses in renewing the furnishings of his official residence(s) subject to the maximum amount specified in column (3) of Schedule I :

Provided that if, when the Governor assumes office, the period which has elapsed since his predecessor assumed office (persons appointed to discharge the functions of the

Governor being disregarded) falls short of five years, the maximum amount so specified shall be decreased by such amount as the President may by order determine :

Provided further that in the case of Governors holding office immediately before the commencement of these rules, the amount admissible to them during their entire term shall be such as the President may by order determine.

(2) The provisions of this rule shall not apply to persons appointed to discharge the functions of the Governor under article 160 of the Constitution of India.

4. Household Establishment.—(1) The total number of officers and other staff of household establishment at official residences shall be as the President may prescribe, from time to time, by an Order, and their scale of pay, allowances, other emoluments and facilities shall be such as are admissible to the State Government officers and other employees of the corresponding posts in the concerned State Government, from time to time.

(2) The officers, and the staff of the household establishment shall be entitled to rent free accommodation and those of the officers and the staff who are not provided any government accommodation shall be allowed house rent allowance at the rates admissible to the State Government officers and other employees of the corresponding posts working in the concerned State Government and in such cases the first charge of ten per cent on the pay shall also be met out of the Governor's allowances.

(3) The staff of the household establishment shall not be allowed overtime allowance.

(4) The officers and staff of the household establishment, who are provided government accommodation, shall be provided free electricity and water subject to the limit laid down by the Governor from time to time but such limit shall not exceed 6-1|4 per cent of the pay of the member of the staff for the supply of both electricity and water :

Provided that out of the limit of 6-1|4 per cent the electricity charges shall not exceed 5 per cent in any case.

(5) Any expenditure on consumption of electricity and water in excess of the limit specified in sub-rule (4) shall be borne by the concerned officer or the member of the staff, as the case may be.

(6) No member of the household establishment shall be allowed free use of official transport for private purposes :

Provided that the staff of the household establishment may be allowed to use Government vehicles on payment of usual charges, subject to availability of vehicles.

(7) The staff of the household establishment shall be entitled to pension and other retirement benefits including medical facilities as are admissible to the concerned State Government employees of the corresponding posts.

(8) The expenditure to be incurred under sub-rule (1) shall be part of the Governor's allowances and shall be drawn separately under the sub-head "Household Establishment".

5. Expenditure on Governor's Secretariat etc.—In addition to the household establishment, the Governor shall be entitled to a separate secretarial staff which shall be provided by the concerned State Government.

(2) The expenditure on the establishment of the Governor's Secretariat and the expenditure on pension and other retirement benefits including medical facilities of the household establishment staff shall be charged on the Consolidated Fund of the concerned State.

(3) The expenditure referred to in sub-rule (2) shall not form part of the Governor's allowances.

6. Allowances of the Governor.—(1) In order that the Governor may be able to discharge conveniently and with dignity the duties of his office, the Governor shall be paid annually the following allowances or grants, namely :—

(a) entertainment allowance.—to be spent for patronising art, culture and music and any unspent portion of the allowance under this sub-head shall lapse at the end of the financial year to which it relates;

(b) hospitality grant.—for meeting hospitality expenses of the official guests and any unspent portion of the grant under this sub-head shall lapse at the end of the financial year to which it relates;

(c) office expenses allowance.—for meeting expenditure on the following items—(i) telephone charges; (ii) service postage; (iii) books and periodicals (iv) stationery and printing; (v) maintenance of motor cycles, scooters and cycles including POL for these vehicles; (vi) miscellaneous expenses :

Provided that any expenditure on the purchase of cycles, scooters or motor cycles shall be met directly by the State Government;

(d) contract allowance.—for being utilised for expenditure on the following items.—(i) special stationery; (ii) laundry contingencies; (iii) sports, (iv) firewood; (v) presents; (vi) soap, cleansing material, insecticides; (vii) liveries; (viii) POL (other than expenditure from tour expenses); (ix) maintenance of cars; (x) library; and (xi) other miscellaneous expenditure;

(e) grant for maintenance and repairs of furnishings.—to be utilised for maintenance and repairs of furnishings of the official residence(s) and|or for the purchase of new items of furniture provided that maximum amount does not exceed the amount specified under this sub-head;

(f) tour expenses grant.—to be utilised for the tour expenses of the Governor and expenditure on POL for cars of official residen-(s) used for tours of the Governor.

(2) The amount admissible under different sub-heads under sub-rule (1) shall be as specified in Schedule II.

(3) (a) No reappropriation shall be permissible within the following sub-heads :

(i) Entertainment Allowance; (ii) Hospitality Allowance; (iii) Office Expenses; (iv) Maintenance and repairs of furnishings of official residence(s);

(b) The Governor may, without exceeding the maximum amount specified in columns (6) and (7) of Schedule II, re-appropriate, whenever necessary, from sub-head "contract allowance" to sub-head "tour expenses" and vice versa.

(4) The amount specified under sub-heads relating to office expenses, maintenance and repairs of furnishings, contract allowance and tour expenses of Schedule II may, in any year, be increased by the amount not expended in previous years under the same sub-heads.

7. Allowances for maintenance of official residence(s).—The Governor shall also be paid such allowances, each year, for the maintenance of Governor's official residence(s) under various sub-heads as specified in Schedule III.

Provided that the Governor may, without exceeding the maximum amount specified in column 7 of the said Schedule reappropriate, whenever necessary, from one sub-head to another sub-head thereof :

Provided further that the maximum amount specified in column 7 of the said Schedule may, in any year, be increased by the amount not expended in the previous years.

8. Travelling Allowance on Assumption or vacation of Office.—(1) The Governor shall be paid an allowance equal to the actual expenses incurred in undertaking journeys for the purposes specified in section 9 of the Act, as travelling allowance for himself and the members of his family and for the transport of his and his family effects.

(2) The expenditure to be incurred under sub-rule (1) shall by charged on the Consolidated Fund of the concerned State but shall not form part of the Governor's allowances.

9. Leave.—The President may grant leave to a Governor for such duration as he may consider necessary.

10. Medical attendance and treatment.—(1) A Governor and members of his family shall be entitled, free of charge to medical attendance, accommodation and treatment on the scale and conditions applicable to the highest ranking member of the All India Services under the All India Services (Medical Attendance) Rules, 1954, as amended from time to time.

(2) While on duty outside India, a Governor shall also be entitled, free of charge, to such medical attendance, accommodation and treatment as may be admissible to the Head of the Indian Mission at that place is at the place of treatment

(3) The State Government shall make adequate provisions for medical facilities for the Governor and his family and the expenditure on this account shall be charged on the Consolidated Fund of the State and shall not form part of the Governors' allowances.

(4) Medical attendance, accommodation and treatment of an Ex-Governor and his family shall be governed by the Rules|Orders issued by the Government of India in the Ministry of Health from time to time.

11. Tours and journeys.—(1) The Governor shall be entitled to requisition a railway saloon for all his journeys within the State and shall be entitled to take with him not more than three persons without payments of any fare for him.

(2) The cost of haulage and requisitioning of saloon under sub-rule (1) shall be met from the sub-head "tour expenses".

(3) If, for his journey within the State by rail, a Governor chooses not be to requisition a saloon under sub-rule (1), he shall be entitled to travel in a four berth compartment or coupe, whether first-class air-conditioned or first-class and during such a journey a Governor shall be entitled to take with him three persons in the case of four berth compartment and one person in the case of a coupe, without any extra charge.

(4) For journeys on official business to places outside the State, a Governor, shall be entitled to travel in a four berth compartment or coupe, whether first-class air-conditioned or first-class and during such a journey, shall be entitled to take with him three persons in the case of a four berth compartment and one person in the case of a coupe, without any extra charge.

(5) The spouse of the Governor may travel within the State by rail for attending functions organised by any organisation or association connected with art, culture, science and literature, and for that purchase may reserve a single seat in first-class air-conditioned or first-class compartment and expenditure for such journeys shall be met—

(i) from the sub-head "tour expenses" if she is not associated in any capacity with that organisation or association; and

(ii) by the organisation or association with which she is associated in any capacity : Provided that this facility shall not be available for private journeys of the spouse of the Governor.

(6) A Governor travelling on duty (but not on non-official business) shall be entitled to travel by air and during such a travel, shall be entitled to take one person with him at government expenses.

(7) A Governor while travelling on duty by air under sub-rule (6), may at his discretion travel in the executive class and a person accompanying him

during such a journey shall be entitled to travel only in the standard class, except the spouse of the Governor who may travel in the executive class.

(8) A Governor shall not be entitled to travel on private business by air at Governoment expenses and shall not also be entitled to take any person with him at Government expenses.

(9) A Governor on his private journey out side the State may travel in a four berth compartment or a coupe, whether first-class air-conditioned or first-class and he shall pay—

(i) the fare for two berths of the appropriate class if he travels in four berths compartment in addition to his own fare;

(ii) for his own fare, if he travels in a coupe; and

(iii) the reservation charges for the compartment or the coupe, as the case may be, and any other expenditure incurred during the journey:

(10) For any journeys performed under sub-rule (9), the cost of one fare only shall be met by the Government from the sub-head "tour expenses" and against that fare the Governor may take any person along with him who need not necessarily be a member of his family.

(11) When a Governor undertakes any journey in connection with any work not connected with his official duties, namely, as Chairman or Member of any Commission, Committee or any other organisation, the expenditure incurred on such journeys shall not be debitable to sub-head "tour expenses" and such expenditure shall be met from the same source from which other expenditure of the Commission, Committee or any other organisation is met.

(12) Where there is not railway station or airport in a State, any journey performed by the Governor or by the spouse of the Governor, for private purposes, to reach the nearest railway station or airport situated in a negihbouring State, shall be deemed to be an official journey.

12. Entitlement of travelling allowance and daily allowance of the household establishment accompanying the Governor.—(1) Any member of the Governor's household establishment accompanying the Governor on his visits within the State or outside the State, whether official or private, shall be treated as on duty and shall be entitled to draw travelling allowance and daily allowance as admissible under the State Government rules.

(2) Any member of the Governor's household establishment accompanying the spouse of the Governor during her journey within the State only shall be treated as on duty and shall be entitled to draw travelling allowance and daily allowance as admissible under the State Government rules :

Provided that no travelling allowance or daily allowance shall be admissible to any member of the Governor's household establishment accompanying any other member of the Governor's family or Governor's personal guest.

13. *Use of motor vehicles by the Governor, etc*.—(1) Any private journeys performed by the Governor outside the State by motor vehicles of the official residence(s) shall be paid for by the Governor at the staff car rates of the State Government.

(2) The spouse of a Governor shall be entitled to use free of charge the motor vehicles of the official residence(s) within the State only and for her journeys outside the State, if not accompanied by the Governor on official duty shall be paid for by the Governor at the Staff car rates of the State Government.

(3) Any other members of the Governor's family or personal guests of the Governor not accompanying the Governor or spouse of the Governor, may be allowed to use motor vehicles of the official residence(s) within the State and charges for such journeys shall be paid for by the Governor at the staff car rates of the State Government.

14. Interpretation.—If any question arises as to the interpretation of these rules, it shall be referred to the Central Government, who shall decide the same.

15. Repeal and saving.—(1) All the orders in force immediately before the commencement of these rules in so far as they relate to matters provided for in these rules are hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal anything done or any action takn under the orders so repealed shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of these rules.

Schedule—I

Official residence(s) of the Governors and maximum amount admissible for renewal of their furnishings.
(see rule 3)

Name of the State	Official residence(s)	Maximum Allowances to Governors for renewal of furnishings (in rupees)
1	2	3
1. Andhra Pradesh	The Government House at Hyderabad	2,10,000
2. Arunachal Pradesh	The Government House at Itanagar	2,40,000
3. Assam	The Government House at Guwahati	2,40,000
4. Bihar	The Government Houses at Patna and Ranchi	3,05,400
5. Gujarat	The Government Houses at Gandhinagar and Raj Bhavan Annexe, Ahmedabad	1,80,000
6. Haryana	The Government House at Chandigarh	1,50,000
7. Himachal Pradesh	The Government House at Shimla	1,80,000
8. Karnataka	The Government Houses at Bangalore and Mysore	1,50,000
9. Kerala	The Government House at Trivandrum	1,50,000
10. Madhya Pradesh	The Government Houses at Bhopal and Pachmarhi	1,80,000
11. Maharashtra	The Government Houses at Bombay, Ganeshkind(Pune) and Nagpur	9,00,000
12. Manipur	The Government House at Imphal	2,40,000
13. Meghalaya	The Government House at Shillong	2,40,000
14. Mizoram	The Government House at Aizawl	2,40,000
15. Nagaland	The Government House at Kohima	1,20,000
16. Orissa	The Government House at Bhubaneshwar	2,76,000
17. Punjab	The Government House at Chandigarh	1,80,000
18. Rajasthan	The Government Houses at Jaipur ane Mount Abu	1,50,000
19. Sikkim	The Government House at Gangtok	1,80,000
20. Tamil Nadu	The Government Houses at Guindy and Octacamund	3,90,000
21. Tripura	The Government House at Agartala	1,20,000
22. Uttar Pradesh	The Government Houses at Lucknow and Nainital	5,59,800
23. West Bengal	The Government Houses at Calcutta and Darjeeling	5,25,000

SCHEDULE—II

(Allowances of Governors in respect of certain matters)

(See rule 6)

Name of the State	Hospitality Expenses	Entertainment Allowance	Office Expenses	Maintenance and repairs of furnishings of Official residence(s)	Contract Allowance	Tour Expenses	Total
1	2	3	4	5	6	7	8
	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.
1. Andhra Pradesh	1,08,000	30,000	1,80,000	72,000	3,24,000	4,80,000	11,94,000
2. Arunachal Pradesh	36,000	9,000	90,000	36,000	1,44,000	5,10,000	8,25,000
3. Assam	45,000	15,000	1,50,000	60,000	1,80,000	3,30,000	7,80,000
4. Bihar	45,000	15,000	1,80,000	84,000	1,92,000	3,48,000	8,64,000
5. Gujarat	1,08,000	30,000	1,80,000	90,000	3,60,000	3,00,000	10,68,000
6. Haryana	60,000	18,000	1,20,000	60,000	3,00,000	2,40,000	7,98,000
7. Himachal Pradesh	60,000	18,000	1,20,000	90,000	3,00,000	2,40,000	8,28,000
8. Karnataka	60,000	30,000	1,50,000	60,000	6,00,000	3,00,000	12,00,000
9. Kerala	54,000	18,000	1,20,000	60,000	3,30,000	1,80,000	7,62,000
10 Madhya Pradesh	72,000	24,000	1,80,000	60,000	3,00,000	3,00,000	9,36,000
11. Maharashtra	1,80,000	30,000	1,80,000	3,00,000	9,00,000	7,50,000	23,40,000
12. Manipur	36,000	9,000	90,000	36,000	1,44,000	2,55,000	5,70,000
13. Meghalaya	36,000	9,000	90,000	36,000	1,44,000	2,55,000	5,70,000
14. Mizoram	36,000	9,000	90,000	36,000	1,44,000	5,10,000	8,25,000
15. Nagaland	24,000	9,000	90,000	15,000	2,40,000	2,50,000	6,28,000
16. Orissa	45,000	15,000	1,20,000	60,000	1,88,400	2,82,000	7,10,400
17. Punjab	60,000	18,000	1,20,000	60,000	3,00,000	3,00,000	8,58,000
18. Rajasthan	72,000	18,000	1,20,000	60,000	3,00,000	3,00,000	8,70,000
19. Sikkim	45,000	18,000	1,20,000	36,000	1,50,000	2,50,000	6,19,000
20. Tamil Nadu	1,20,000	30,000	1,80,000	1,50,000	6,00,000	3,00,000	13,80,000
21. Tripura	18,000	5,000	90,000	12,000	2,40,000	2,60,000	6,25,000
22. Uttar Pradesh	1,14,000	30,000	1,80,000	90,000	3,00,000	6,96,000	14,10,000
23. West Bengal	1,35,000	30,000	1,80,000	1,50,000	7,80,000	2,76,000	15,51,000

SCHEDULE—III

Allowances for the maintenance of Official Residences

(See rule 7)

Name of the State	Repairs	Gardens	Electricity	Water	Improvement	Total
1	2	3	4	5	6	7
	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.
1. Andhra Pradesh	2,40,000	60,000	2,16,000	60,000	84,000	6,60,000
2. Arunachal Pradesh	2,60,000	1,20,000	1,44,000	21,000	45,000	5,90,000
3. Assam	94,200	78,600	33,600	33,600	90,000	3,30,000
4. Bihar	3,72,000	1,38,000	84,000	57,000	1,50,000	8,01,000
5. Gujarat	2,40,000	1,56,000	1,20,000	72,000	72,000	6,60,000
6. Haryana	1,17,000	1,17,000	81,000	54,000	54,000	4,23,000
7. Himachal Pradesh	1,20,000	1,08,000	90,000	33,000	30,000	3,81,000
8. Karnataka	3,00,000	3,00,000	1,50,000	1,50,000	3,00,000	12,00,000
9. Kerala	2,28,000	1,20,000	90,000	42,000	1,20,000	6,00,000
10. Madhya Pradesh	1,74,000	1,56,000	60,000	6,000	60,000	4,56,000
11. Maharashtra	22,62,000	3,00,000	4,08,000	3,00,000	3,60,000	36,30,000
12. Manipur	2,60,000	1,20,000	1,44,000	21,000	45,000	5,90,000
13. Meghalaya	2,60,000	1,20,000	1,44,000	21,000	45,000	5,90,000
14. Mizoram	2,60,000	1,20,000	1,44,000	21,000	45'000	5,90,000
15. Nagaland	1,08,000	90,000	90,000	12,000	45,000	3,45,000
16. Orissa	1,53,000	59,400	1,17,000	38,400	39,000	4,06,800
17. Punjab	1,56,000	1,56,000	1,08,000	72,000	72,000	5,64,000
18. Rajasthan	1,74,000	1,56,000	60,000	30,000	60,000	4,80,000
19. Sikkim	30,000	60,000	30,000	18,000	30,000	1,68,000
20. Tamil Nadu	6,18,000	3,84,000	3,30,000	1,02,000	3,00,000	17,34,000
21. Tripura	1,80,000	1,20,000	1,44,000	42,000	1,20,000	6,06,000
22. Uttar Pradesh	4,80,000	2,70,000	1,20,000	90,000	1,80,000	11,40,000
23. West Bengal	17,94,000	4,80,000	2,70,000	9,00,000	96,000	35,40,000

[F.No. 20/1/82-M&G(ii)]
I.P. GUPTA, Addl. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1987